The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 17 Oct, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 & 3 : International Relations & Indian Economy / Prelims	रूसी तेल आयात को लेकर ट्रंप और विदेश मंत्रालय में मतभेद
Page 07 Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims	डोपामाइन ओवरडोज़: कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे दिमाग को रीवायर कर रही है
Page 08 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	भारत के कार्बन बाजार के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें
Page 09 Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims	क्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण ज़मीन से घिरा होना है?
Page 10 Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims	राज्यों के लिए फिस्कल स्पेस बहाल करना
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : Indian Polity	संवैधानिक इतिहास में बदलाव की एक व्याख्या

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Page 01 : GS 2 & 3 : International Relations & Indian Economy / Prelims

भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात पर बहस ने एक बार फिर रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक राजनयिक दबावों के बीच नई दिल्ली के नाजुक संतुलन को ध्यान में ला दिया है। यूक्रेन संघर्ष के बाद मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच, अमेरिका ने भागीदारों से रूस के साथ ऊर्जा व्यापार को सीमित करने का आग्रह किया है। हालांकि, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों और उपभोक्ता हितों से प्रेरित होकर एक स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देते हुए रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के बीच हालिया आदान-प्रदान रणनीतिक व्यावहारिकता और भू-राजनीतिक संरेखण के बीच चल रहे तनाव को दर्शाता है।

Trump and MEA at odds over Russian oil imports

Trump claims Modi gave commitment to stop buying oil from Russia 'soon'; Ministry denies the leaders discussed the issue, but says govt. is 'broad-basing' and 'diversifying' its energy sources

Suhasini Haidar
NEW DELHI

India and the United States continued to differ publicly over Russian oil as U.S. President Donald Trump said he had been assured by Prime Minister Narendra Modi that India will stop buying oil from Russia, while the Ministry of External Affairs maintained the two leaders had not spoken about the issue.

However, the MEA said that India was "broad-basing" and "diversifying" its sources of energy according to market needs, and did not specifically deny the claim that it was reducing its intake.

Bone of contention

The subject of Russian oil, which has led to the U.S. imposing penalty tariffs on India, is also believed to be holding up trade talks between the two countries.

While the government has consistently denied it would bow to pressure, data analysed by *The Hindu* showed that oil public sector undertakings have dropped their Russian imports by as much as 45% between June and September this year, even though Russia remains India's biggest supplier overall.

"I am not aware of any conversation yesterday between the two leaders," MEA spokesperson Randhir Jaiswal told reporters here on Thursday, also clarifying that a call between Mr. Modi and Mr. Trump last Thursday had only dealt with the Gaza peace plan and India-U.S. trade issues.

On Wednesday, Mr. Trump had said he was confident that India would end its oil imports "soon" but not "immediately".

"I was not happy that India was buying oil, and [PM Modi] assured me today that they will not be buying oil from Russia," Mr. Trump told reporters at the White House, with U.S. Ambassador-designate to Delhi Sergio Gor also present.

"It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon," Mr. Trump said, adding, "That's a big step. Now we're going to get China to do the same thing."

On Thursday, the Chinese Ministry of Foreign Affairs slammed the U.S. for "unilateral bullying" over its "legitimate" imports from Russia.

Going on to praise Mr. Modi as a "great man" who "loves Trump", Mr. Trump said he did not want to "destroy [Mr. Modi's] political career".

"I've watched India for years. It's an incredible country, and every single year you'd have a new leader," Mr. Trump said, adding: "My friend has been there now for a long time."

"It has been [India's] consistent priority to safeguard the interests of the Indian consumer in a volatile energy scenario," the statement said, referring to stable prices and secure supplies as "twin goals". "This includes broad-basing our energy sourcing and diversifying as appropriate to meet market conditions."

The MEA was more direct on its response to U.K. sanctions on Nayara, an Indian refiner owned by Russian oil major Rosneft.

"India does not subscribe to any unilateral sanctions... There should be no double standards, especially when it comes to energy trade," Mr. Jaiswal said.

Trump vs MEA

India and the U.S. have been at loggerheads over the former's purchase of Russian oil, and New Delhi has consistently denied it will bow to pressure

- Trump says Modi committed on Oct. 15 to **ending Russian oil imports soon**
- MEA says there was **no conversation between leaders that day**, no reference to Russian oil in Oct. 9 call too
- U.S. Ambassador-designate to India Sergio Gor met Modi on Oct. 11 and later Trump on Oct. 15; However, it is **unclear if he conveyed India's message**

MEA on Oct. 16 says priority is to protect interests of Indians, broad-basing energy sources

"I was not happy that India was buying oil, and [PM Modi] assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big step. Now we're going to get China to do the same thing... He [Mr. Modi] loves Trump... I don't want to destroy his political career"
DONALD TRUMP, U.S. President

Modi outsourced key decisions to the U.S.: Congress

NEW DELHI
Congress leader Rahul Gandhi said PM Modi is "frightened" of U.S. President Donald Trump. In a post on X, he said, "[Modi] allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil..." » PAGE 4

China defends oil purchase, slams U.S. for 'bullying'

BEIJING
China said that its purchases of Russian oil were "legitimate" and decried recent "unilateral bullying" measures by the U.S. as the trade row between the two countries continues to intensify. » PAGE 14

समस्या अवलोकन

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत जल्द ही रूसी तेल का आयात बंद कर देगा।
- विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया: विदेश मंत्रालय ने ऐसी किसी भी चर्चा से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि हाल ही में मोदी-ट्रम्प कॉल गाजा और व्यापार के मुद्दों पर केंद्रित था, न कि रूसी तेल पर।
- भारत का रुख: भारत ने बाहरी दबाव के आगे झुके बिना सुरक्षित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए "ऊर्जा स्रोतों को व्यापक आधार देने और विविधता लाने" की अपनी रणनीति दोहराई।

प्रमुख डेटा और विकास

- भारत रूसी क्रूड का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात ~45% (जून-सितंबर 2025) तक गिर गया है।
- अमेरिका ने रूस के साथ निरंतर ऊर्जा संबंधों को लेकर भारत पर जुर्माना शुल्क लगा दिया है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में प्रगति में देरी हो रही है।

- चीन ने अपने स्वयं के रूसी तेल आयात का बचाव करते हुए "एकतरफा बदमाशी" के लिए अमेरिका की आलोचना की।
- विदेश मंत्रालय ने भारत के इस रुख की पुष्टि की कि वह 'एकतरफा प्रतिबंधों' को स्वीकार नहीं करता है और ऊर्जा व्यापार में 'दोहरे मानदंडों' का विरोध करता है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
ऊर्जा सुरक्षा	तेल सोर्सिंग में सामर्थ्य, स्थिरता और विविधीकरण सुनिश्चित करना।
रणनीतिक स्वायत्तता	यह अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत के स्वतंत्र रुख को दर्शाता है।
भुगतान संतुलन (बीओपी)	रियायती रूसी तेल आयात बिल को नियंत्रित करने में मदद करता है।
भारत-अमेरिका संबंध	गहरे बढ़ते रणनीतिक सहयोग के बीच उभरता टकराव।
वैश्विक भू-राजनीति	यूक्रेन के बाद की वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीय तनाव को दर्शाता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

a. ऊर्जा सुरक्षा और वास्तविक राजनीति

- भारत का दृष्टिकोण व्यावहारिक यथार्थवाद को दर्शाता है - सस्ते ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से घरेलू स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता देना।
- रूस, मध्य पूर्व और अफ्रीका से आयात का विविधीकरण आपूर्ति के झटके के खिलाफ लचीलापन बढ़ाता है।

b. राजनयिक संतुलन

- भारत वाशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंधों को संतुलित करना जारी रखता है , गठबंधन की राजनीति पर राष्ट्रीय हित पर जोर देता है।
- विदेश मंत्रालय का इनकार भारत के सार्वजनिक टकराव से बचने के इरादे का संकेत देता है, जबकि चुपचाप अपने आयात मिश्रण को फिर से व्यवस्थित करता है।

c. आर्थिक आयाम

- रूस पर निर्भरता कम होने से पश्चिमी व्यापार तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन अल्पावधि में आयात लागत बढ़ सकती है।
- रियायती रूसी तेल प्रवाह बनाए रखने से राजकोषीय स्थिरता और रुपये के बाहरी संतुलन का समर्थन होता है।

d. द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भ

- भारत-अमेरिका संबंध समग्र रूप से मजबूत बने हुए हैं, विशेष रूप से रक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत सहयोग में, हालांकि ऊर्जा नीति पर अस्थायी टकराव बना हुआ है।

- यह प्रकरण बदलते वैश्विक शक्ति मैट्रिक्स को भी रेखांकित करता है, जहां राष्ट्र महान-शक्ति प्रतिद्वंद्विता के बीच स्वायत्तता का दावा करते हैं।

नीति का महत्व

- ऊर्जा नीति: एलएनजी बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और अफ्रीकी ऊर्जा साझेदारी के विस्तार की आवश्यकता।
- कूटनीति: भारत के "रणनीतिक स्वायत्तता" के सिद्धांत और ब्लॉक की राजनीति के प्रतिरोध को पुष्ट करता है।
- आर्थिक लचीलापन: व्यापक सोर्सिंग किसी एक आपूर्तिकर्ता या भू-राजनीतिक ब्लॉक पर अत्यधिक निर्भरता को रोकती है।
- दीर्घकालिक रणनीति: आत्मनिर्भर और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के साथ संरेखण।

रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
बाहरी क्षेत्र की स्थिरता	रूसी छूट भारत के बीओपी को स्थिर करने में मदद करती है।
भारत-अमेरिका संबंध	मामूली तनाव, लेकिन समग्र सहयोग जारी रहने की संभावना है।
ऊर्जा कूटनीति	भारत वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्वायत्तता पर जोर दे रहा है।
वैश्विक राजनीति	चीन की अवज्ञा बनाम अमेरिकी दबाव पर प्रकाश डाला - भारत बीच का रास्ता तय कर रहा है।
नीति निरंतरता	घरेलू जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक आयात निर्णय।

आगे की चुनौतियाँ

- भू-राजनीतिक दबाव: वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच रूस और अमेरिका दोनों के साथ संबंधों का प्रबंधन।
- मूल्य अस्थिरता: वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव राजकोषीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है।
- स्वीकृति जोखिम: नायरा एनर्जी जैसे रिफाइनरों का पश्चिमी प्रतिबंधों के लिए एक्सपोजर।
- ऊर्जा संक्रमण: जीवाश्म-ईंधन निर्भरता को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी लाना।

निष्कर्ष:

रूसी तेल आयात पर अमेरिकी दबाव के प्रति भारत की प्रतिक्रिया उसकी संतुलित और रुचि-संचालित कूटनीति का प्रतीक है। जबकि वाशिंगटन मॉस्को के खिलाफ एकजुटता चाहता है, नई दिल्ली ऊर्जा सामर्थ्य, आपूर्ति सुरक्षा और घरेलू स्थिरता को प्राथमिकता देता है। यह प्रकरण रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, भले ही यह वैश्विक साझेदारी को गहरा करता है। आगे बढ़ते हुए, ऊर्जा विविधीकरण और स्थिरता प्राप्त करना "विकसित भारत @2047" के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां भारत दुनिया के साथ मजबूती और आत्मनिर्भरता की स्थिति में जुड़ता है।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: भारत के कच्चे तेल के आयात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रूस हाल के वर्षों में भारत के कच्चे तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है।

2. भारत का तेल आयात पूरी तरह से सरकार-से-सरकार समझौतों के माध्यम से तय किया जाता है।

3. भारत की ऊर्जा सोर्सिंग रणनीति निर्धारित करने में विदेश मंत्रालय (MEA) की प्राथमिक भूमिका है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2 और 3

उत्तर : a)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

□□□□□ □□□□□□

प्रश्न: भारत की ऊर्जा कूटनीति रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक जिम्मेदारी के बीच संतुलन को दर्शाती है। रूसी तेल आयात पर अमेरिका के साथ हालिया तनाव के प्रकाश में, चर्चा करें। (150 शब्द)

Page 07 : GS 2 : Social Justice / Prelims

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

डोपामाइन, जिसे आमतौर पर "फील-गुड" न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जाना जाता है, प्रेरणा, इनाम और आनंद में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। जबकि ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक पुरस्कारों और मादक द्रव्यों की लत से जुड़ा हुआ है, समकालीन डिजिटल जीवन शैली - सोशल मीडिया, लघु वीडियो और निरंतर सूचनाओं की विशेषता - ने डोपामाइन को दोधारी तलवार में बदल दिया है। मस्तिष्क की इनाम प्रणाली की अत्यधिक उत्तेजना तेजी से व्यसन जैसे व्यवहार, भावनात्मक अस्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का कारण बन रही है, खासकर किशोरों और युवा वयस्कों के बीच। मानसिक कल्याण और संतुलित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस न्यूरोबायोलॉजिकल और सामाजिक घटना को समझना महत्वपूर्ण है।

समस्या अवलोकन

- **मुख्य चिंता:** आधुनिक तकनीक मेसोलिम्बिक डोपामाइन मार्ग को अत्यधिक उत्तेजित करती है, बाध्यकारी व्यवहार पैटर्न बनाती है और आधारभूत खुशी को कम करती है।
- **युवा प्रभाव:** किशोर और युवा वयस्क मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी के कारण विशेष रूप से कमजोर होते हैं, जिससे वे ध्यान की कमी, चिंता और बाध्यकारी जांच व्यवहार के लिए प्रवण हो जाते हैं।
- **तंत्र:** सोशल मीडिया जुड़ाव, सूचनाएं और एल्गोरिदम-संचालित सामग्री दवा की तरह आंतरायिक सुदृढीकरण की नकल करती है, जो नशे की लत पदार्थों के समान नाभिक accumbens को सक्रिय करती है।

Dopamine overdose: how modern lifestyles are rewiring our brains

Contemporary life has made dopamine a double-edged sword that both stimulates productivity and feeds addiction; bringing back balance is key: breaks from devices, regular movement and meaningful social connections can all help stabilise dopamine levels and enhance mental well-being

Pretty Duggar Gupta

If there were a chemical formula for happiness, dopamine would be at its core. Often called the "feel-good" neurotransmitter, dopamine drives motivation, reward, and pleasure, whether from a good meal, an achievement, or a meaningful relationship. From drug addictions to social media marathons, contemporary life has made dopamine a double-edged sword that both stimulates productivity and feeds addiction.

Dopamine is a chemical signal that conveys pleasure and thus a sense of reward. Each time something happens that makes us happy,such as eating chocolate or receiving a compliment, our brain releases dopamine, prompting us to act in the same manner again. On a neurobiological level, this is largely contingent on the mesolimbic pathway from the ventral tegmental area (VTA) to the nucleus accumbens, a central part of the brain's reward pathways. The mesolimbic pathway reinforces behaviours we perceive as constructive or pleasurable, along with reward prediction and a motivation to learn.

Certain times, these processes are commandeered by addictive drugs, including cocaine, nicotine, or alcohol. Such drugs induce massive dopamine surges, overwhelming the reward centre of the brain. Over time however, the brain gets desensitised, requiring more doses of the addictive substance in order to feel normal. This is where addiction begins – not from pleasure itself, but from the brain trying to bring balance back.

From substances to screens

Drugs used to be the primary cause of dopamine overload, but now, technology is the new push. Every ping, like, and notification serves to deliver tiny doses of dopamine, delivered intermittently, to promote user engagement in a reward schedule that best resembles a slot machine. Social media, short videos, reels, and streaming services exploit this gap, producing dependency with their endless cycle of suspense and satisfaction.

Although scrolling on Instagram or watching endless short videos may feel harmless, neuroscientists have shown that the brain processes the kind of stimulation presented by technology similarly to actual drug use. Such use promotes compulsive checking behaviours, fractured attention, anxiety, or withdrawal when disconnected. Functional MRI studies have shown overlapping activation in the nucleus accumbens during social media engagement and substance use, supporting the idea that digital stimuli can trigger the same reward circuits that drive addiction.

What is more concerning is that dopamine-driven design is not coincidental – it is a result of behavioural engineering, in which algorithms find out what rewards you the most and serve you more of it.

Young adults and teenagers, who are still learning how to manage their emotions and impulses, are especially susceptible. Research indicates that adolescents who report spending more than three hours a day on social media report substantially higher levels of anxiety and depressive symptoms. The adolescent brain is particularly plastic in development. This means that under-stimulation from the world around them and overstimulation from technology may, quickly yet casually, shape their reward circuits – creating hyper-short attention spans and emotional instability. Excessive screen time is shown by research to change the sensitivity of dopamine receptors, making it more difficult to find pleasure in daily life. Short of that, our normal baseline happiness is decreasing, while our appetites for stimulation become stronger.

An overload of dopamine does not indicate that we are off the charts happy; it suggests that our brain's reward system may be fatigued. By constantly seeking out stimulation, we are unknowingly setting ourselves up for burnout. The implications may be slow and stealthy at first: the experience of losing motivation when performing a normal task as it feels bland compared to an immediate sense of stability experienced while waiting for digital affirmation or enjoying the pharmacologic effects of a substance. Eventually, wear and tear will dull our emotional responses to regular experiences, for instance, the ability to experience, joy, and will interrupt sleep, shorten our attention span and begin to deteriorate our mental health with anxiety, depression and poor self-esteem.

It is possible to use social media engagement to stimulate reward circuits in the brain that resemble what drives some to addiction. When the brain becomes accustomed to constant spikes of pleasure and begins screaming for more, potential manifestations include addiction, whether social media, video games, or drugs.

Reclaiming balance

The solution, of course, is not to eliminate dopamine, but rather to bring it back in balance. "Dopamine fasting" refers to taking a break from the defeating pleasure and excitement our brains tend to rely on and instead, attempting to retrain our brains to function appropriately with a more moderate and sustainable level of happiness when engaging in slower and deeper experiences. Taking time away from constant phone reminders, silencing emails, taking a break from your devices, making your devices greyscale, or simply instituting a tech break can help your mind reset its rhythm.

Regular movement and moderate engagement with mindfulness will allow you to experience dopamine naturally and at a more stable and healthy level, instead of the non-stop hyper-stimulating level we are used to in the present. Focusing on meaningful activities – deep work, learning new skills – also ushers in enjoyable experiences with slower, more lasting rewards.

The most important return to balance comes with real human connection – a good old-fashioned conversation, a laugh with a friend, or time spent with family that provides a level of happiness that no social media 'likes' can match. Ensuring good sleep, good nutrition, and emotional awareness helps stabilise dopamine levels and grounds our moods.

(Dr. Pretty Duggar Gupta is consultant psychiatrist, Aster Hospital, Bengaluru. pretty.gupta@asterhospital.in)

Worrying trend: Although scrolling on Instagram or watching endless short videos may feel harmless, neuroscientists have shown that the brain processes the kind of stimulation presented by technology similarly to actual drug use. K.R. DEEPAK

THE GIST

- Dopamine is a chemical signal that conveys pleasure and thus a sense of reward. Each time something happens that makes us happy, such as eating chocolate or receiving a compliment, our brain releases dopamine, prompting us to act in the same manner again
- An overload of dopamine does not indicate that we are off the charts happy; it suggests that our brain's reward system may be fatigued. By constantly seeking out stimulation, we are unknowingly setting ourselves up for burnout
- Regular movement and moderate engagement with mindfulness will allow you to experience dopamine naturally and at a more stable and healthy level, instead of the non-stop hyper-stimulating level we are used to in the present. Focusing on meaningful activities also ushers in enjoyable experiences with slower, more lasting rewards

मुख्य अवलोकन

- **तंत्रिका विज्ञान साक्ष्य:** कार्यात्मक एमआरआई अध्ययन डिजिटल सगाई और पदार्थ उपयोग दोनों के लिए इनाम सर्किट में अतिव्यापी सक्रियण का संकेत देते हैं।
- **व्यवहार संबंधी रुझान:** अत्यधिक स्क्रीन समय कम ध्यान अवधि, भावनात्मक अस्थिरता, बाध्यकारी जांच और सामान्य गतिविधियों से आनंद प्राप्त करने की क्षमता कम हो जाती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव:** चिंता, अवसाद, नींद की गड़बड़ी और कम आत्मसम्मान डोपामाइन डिसरेग्यूलेशन से जुड़े हुए हैं।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
तंत्रिका जीव विज्ञान	इनाम, प्रेरणा और व्यसन मार्गों में डोपामाइन की भूमिका।
मानसिक स्वास्थ्य	डिजिटल ओवरस्टिम्यूलेशन के कारण बढ़ती चिंता और अवसाद।
व्यसन अध्ययन	डिजिटल लत एक न्यूरोबायोलॉजिकल स्तर पर मादक द्रव्यों की लत के समानांतर है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य	निवारक मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए निहितार्थ।
जीवन शैली और उत्पादकता	अत्यधिक उत्तेजना निरंतर ध्यान केंद्रित करने और गहरे काम करने की क्षमता को कम कर देती है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **न्यूरोबायोलॉजिकल निहितार्थ:** क्रोनिक डोपामाइन स्पाइक्स इनाम प्रणाली को असंवेदनशील बनाते हैं, जिससे उच्च उत्तेजना मांगने वाले व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
- **व्यवहार संबंधी निहितार्थ:** डिजिटल मीडिया का अति प्रयोग बाध्यकारी व्यवहार, खंडित ध्यान और भावनात्मक अस्थिरता पैदा करता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं:** इनाम प्रणाली की थकान प्राकृतिक पुरस्कारों से प्रेरणा और खुशी को कम करती है, जिससे बर्नआउट और एनहेडोनिया होता है।
- **नीति और सामाजिक दृष्टिकोण:** बढ़ती डिजिटल लत जागरूकता अभियानों, विनियमित स्क्रीन समय और इनाम के मार्गों को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप की मांग करती है।

समाधान और नीति महत्व

- **डोपामाइन उपवास:** इनाम प्रणाली को पुन: व्यवस्थित करने के लिए उच्च-उत्तेजना मीडिया से अस्थायी ब्रेक।
- **माइंडफुल एंगेजमेंट:** धीमी, सार्थक गतिविधियों जैसे गहन काम, कौशल विकास या शौक पर ध्यान केंद्रित करें।
- **शारीरिक और सामाजिक हस्तक्षेप:** प्राकृतिक रूप से डोपामाइन को स्थिर करने के लिए नियमित व्यायाम, उचित नींद, पोषण और गुणवत्तापूर्ण सामाजिक संपर्क।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय:** डिजिटल लत को रोकने के लिए शिक्षा, माता-पिता का मार्गदर्शन और स्कूल-आधारित हस्तक्षेप, खासकर किशोरों में।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
युवा मानसिक स्वास्थ्य	दीर्घकालिक बाध्यकारी व्यवहार को रोकने के लिए हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण खिड़की।
डिजिटल नीति	स्क्रीन टाइम, ऐप डिज़ाइन और इनाम-आधारित एल्गोरिदम पर दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।
कार्य उत्पादकता	अत्यधिक उत्तेजना सार्थक कार्यों के लिए ध्यान बनाए रखने की क्षमता को कम कर देती है।
जन जागरूकता	जिम्मेदार तकनीकी उपयोग और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है।
स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली	डिजिटल लत से संबंधित परामर्श और मनोरोग सेवाओं की बढ़ती मांग।

आगे की चुनौतियाँ

□□□□□ □□□□□□

- डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से विकास।
- एल्गोरिथम व्यवहार इंजीनियरिंग बाध्यकारी उपयोग को मजबूत करती है।
- मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी के कारण किशोरों की उच्च भेद्यता।
- चिंता, अवसाद और ध्यान विकारों से मानसिक स्वास्थ्य का बोझ बढ़ रहा है।
- गतिहीन आदतों और सामाजिक अलगाव से जीवनशैली का असंतुलन।

निष्कर्ष:

आधुनिक जीवन शैली ने डोपामाइन को एक प्राकृतिक प्रेरक से व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के संभावित स्रोत में बदल दिया है। जबकि प्रौद्योगिकी पुरस्कार और प्रेरणा प्रदान करती है, अतिउत्तेजना मस्तिष्क को फिर से तार देती है, आधारभूत खुशी और ध्यान अवधि को कम करती है। सचेत जुड़ाव, शारीरिक गतिविधि, सामाजिक बातचीत और नियंत्रित प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से संतुलन बहाल करना आवश्यक है। नीतिगत पहल, जन जागरूकता और व्यक्तिगत रणनीतियों को विशेष रूप से युवाओं के बीच स्वस्थ न्यूरोकॉग्निटिव विकास और मानसिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए, जिससे मानसिक स्वास्थ्य से समझौता किए बिना जिम्मेदारी से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सक्षम समाज को सक्षम बनाया जा सके।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: डोपामाइन मुख्य रूप से इससे जुड़ा हुआ है:

a) तनाव प्रतिक्रिया

b) इनाम, प्रेरणा और आनंद

c) प्रतिरक्षा प्रणाली विनियमन

d) नींद-जागने का चक्र

उत्तर: b)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: चर्चा करें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कैसे डोपामाइन ओवरलोड में योगदान दे रहे हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नतीजों पर रोशनी डालें**,** खासकर किशोरों में**?**

Page 08 : GS 3 : Environment / Prelims

जैसे-जैसे भारत कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, कार्बन क्रेडिट बाजार उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में उभर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण और टिकाऊ कृषि के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट, विकासशील देशों में जलवायु-सकारात्मक प्रथाओं को पुरस्कृत करते हुए फर्मों को उत्सर्जन की भरपाई करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। हालाँकि, वैश्विक परियोजनाओं के अनुभव, विशेष रूप से केन्या में, स्थानीय समुदायों को हाशिए पर रखने, प्रथागत भूमि अधिकारों को कमजोर करने और निष्कर्षण शक्ति संरचनाओं की नकल करने के जोखिमों को उजागर करते हैं। भारत के लिए, **अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) में इक्विटी, सहमति और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सामाजिक न्याय और सामुदायिक कल्याण के साथ जलवायु लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है।**

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Ensure safeguards for India's carbon market

K.S. Aditya

is a Scientist at the Indian Council of Agricultural Research-Indian Agricultural Research Institute (ICAR-IARI), New Delhi

Adeeth A.G. Cariappa

is an Environmental and Resource Economist at the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)-India

As India builds its carbon market, the lessons from global failures show why protecting farmers and communities must come first

The growth-driven model of development, rooted in the Industrial Revolution, has already pushed planetary boundaries beyond safe limits. Some call for "degrowth" to address environmental damage, but this is neither just nor feasible for developing countries that are still grappling with poverty and hunger. A more equitable path lies in decoupling growth from environmental harm. In other words, countries must find ways to reduce poverty and expand their economies without repeating the high-pollution, high-emission model of the past.

This can be done by relying on cleaner technologies, renewable energy and sustainable farming practices. In India, for instance, the rapid expansion of solar energy and micro-irrigation illustrate how growth and sustainability can go hand in hand.

On carbon credit

Carbon crediting is one such tool. A carbon credit represents a certified reduction or removal of greenhouse gases, expressed in carbon dioxide (CO_2) -equivalents. These can be generated through mitigation activities such as renewable energy or sequestration efforts such as reforestation, agroforestry and biochar. Firms buy them to offset emissions while transitioning to cleaner processes, ideally rewarding developing countries for adopting low-carbon practices.

Carbon credits are booming, with 175 million-180 million retired annually, primarily from renewable energy and nature-based projects such as REDD+ and afforestation. India is also building its own carbon market through the Carbon Credit Trading Scheme (CCTS). The scheme will set emission-intensity benchmarks for energy-intensive sectors and include voluntary offsets. A national registry and trading platform will manage transactions, with draft methods for biomass, compressed biogas, and low-emission rice cultivation already released.

Globally, agriculture-based projects lag despite high potential. Of 64 Indian agricultural projects listed under Verra, only four are registered and none has issued credits. CIMMYT's research links this to weak farmer engagement, training and follow-up, especially among smallholders and marginalised caste groups.

Carbon markets and the risk of exploitation

Carbon projects are meant to reward communities at the frontlines of climate action. But without safeguards, they risk replicating extractive power structures, echoing the logic of colonial plantations. Rising carbon prices only heighten this risk. The Northern Kenya Rangelands Carbon Project offers a cautionary tale. Launched in 2012, it spanned 1.9 million hectares and sought to remove 50 million tonnes of CO_2 over 30 years. Though framed as community-led, the project has drawn scrutiny for bypassing consent and weakening local land rights, raising critical questions about who truly controls and benefits from carbon projects. The project introduced rotational grazing and rangeland restoration, but cracks soon appeared.

In 2023, Verra suspended credit issuance after advocacy groups highlighted flaws in soil carbon measurement and a lack of free, prior, and informed consent (FPIC) from indigenous communities. Petitioners alleged that the conservancies were created without public consultation, on unregistered community land, and enforced through armed rangers. In 2025, a Kenyan court confirmed that key conservancies had bypassed public participation, prompting a second suspension by Verra. Community conservancies, common across Kenya, are locally managed bodies meant to promote sustainability and protect livelihoods through elected governance. In principle, they embody decentralised, community-driven resource management. Critics argue that the project's top-down grazing restrictions and opaque governance structures mirror colonial-era resource control, infringing on pastoralist land rights and underscoring the urgent need for community-led, decolonised carbon initiatives.

Similarly, the Lake Turkana Wind Power project (Kenya) fenced 1,50,000 acres of community rangeland, cutting off herders from grazing routes and water; it raised the question of whether sustainability is advancing at the expense of the vulnerable.

India could face similar risks. Carbon projects in afforestation, reforestation and agriculture often extend into areas with customary land use. Plantations on village commons or forest fringes could disrupt access to grazing, fuelwood and forest produce without community consent. Agricultural projects have already shown signs of bypassing marginalised caste farmers while delivering few benefits. The Kenyan judgment is a timely warning: unless land rights, consent and fair benefit-sharing are secured, India's carbon market risks reproducing extractive models under the guise of climate action.

Why carbon projects are vulnerable

Carbon projects can slip into "modern plantations" when powerful companies dominate and local communities are sidelined. In India, farmers and tribal communities often face information and power asymmetries that enable opaque deals and unfair benefit-sharing. Developers are not required to disclose benefit-sharing arrangements, and practices are often imposed top-down, with little regard for local contexts or consent.

India's Carbon Credit Trading Scheme, while ambitious, focuses mainly on procedures and compliance, with scant attention to land rights, FPIC, and equitable revenue distribution. These blind spots may expose vulnerable groups to exclusion and exploitation as the market expands.

Overregulation is not the solution, as burdensome legal frameworks could discourage even well-intentioned actors. What India needs is a balanced, lightweight regulatory architecture that guarantees transparency, formalises benefit-sharing, and protects community rights, without creating bureaucratic choke points.

Achieving this will require stakeholder consultation, adaptive regulation and a clear-eyed recognition of risks. Only then can India build trust and integrity in its carbon market while ensuring that climate action does not come at the cost of justice.

समस्या अवलोकन

- **भारत में कार्बन क्रेडिट:** भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना उत्सर्जन-तीव्रता वाले बेंचमार्क निर्धारित करती है और स्वैच्छिक ऑफसेट की अनुमति देती है। बायोमास, कम उत्सर्जन वाले चावल और संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं के लिए मसौदा पद्धतियां मौजूद हैं।

- **वैश्विक सबक:** उत्तरी केन्या रेंजलैंड्स और लेक तुर्काना विंड पावर जैसी परियोजनाएं सामुदायिक सहमति को दरकिनार करने, भूमि तक पहुंच को प्रतिबंधित करने और टॉप-डाउन शासन लागू करने के जोखिमों को उजागर करती हैं।
- **घरेलू कमजोरियां:** वनीकरण, पुनर्वनीकरण और कृषि कार्बन परियोजनाएं गांव के आम इलाकों या वन सीमाओं के साथ प्रतिच्छेद कर सकती हैं, संभावित रूप से स्थानीय आजीविका को बाधित कर सकती हैं और छोटे किसानों या जाति-आधारित किसानों को हाशिए पर डाल सकती हैं।

मुख्य अवलोकन

- **बाजार वृद्धि:** 175-180 मिलियन कार्बन क्रेडिट सालाना सेवानिवृत्त होते हैं, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा और प्रकृति-आधारित परियोजनाओं से। उच्च क्षमता के बावजूद कृषि परियोजनाएं पिछड़ जाती हैं।
- **सामुदायिक जोखिम:** शक्ति असंतुलन, अपारदर्शी लाभ-साझाकरण, और पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी) की कमी समुदायों को शोषण के लिए उजागर करती है।
- **नियामक अंतर:** भारत का CCTS प्रक्रियात्मक अनुपालन पर जोर देता है लेकिन भूमि अधिकारों, FPIC और समान राजस्व वितरण के लिए सुरक्षा उपायों का अभाव है।
- **अतिविनियमन नुकसान:** अत्यधिक कानूनी बोझ भागीदारी को हतोत्साहित कर सकता है; एक **संतुलित नियामक दृष्टिकोण** की आवश्यकता है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
जलवायु नीति और कार्बन बाजार	बाजार तंत्र के माध्यम से कम कार्बन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।
सतत कृषि	जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देते हुए ऋण उत्पन्न करने की क्षमता।
सामुदायिक अधिकार और न्याय	एफपीआईसी, भूमि अधिकार और उचित लाभ-साझाकरण आवश्यक सुरक्षा उपाय हैं।
वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास	केन्याई कार्बन परियोजनाएं शासन और इक्विटी पर चेतावनी सबक प्रदान करती हैं।
हरित विकास और विघटन	कार्बन बाजार पर्यावरणीय नुकसान से आर्थिक विकास को अलग करने का समर्थन करते हैं।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व:** कार्बन बाजार भारत के ऊर्जा परिवर्तन को गति दे सकते हैं, कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि का समर्थन कर सकते हैं।
- **सामाजिक आयाम:** सुरक्षा उपायों के बिना, कार्बन परियोजनाएं **औपनिवेशिक निष्कर्षण मॉडल की नकल करने**, कमजोर समुदायों को दरकिनार करने और असमान लाभ वितरण का कारण बनने का जोखिम उठाती हैं।

- **शासन की चुनौतियाँ:** ग्रामीण भारत में असममित जानकारी और टॉप-डाउन कार्यान्वयन बिजली असंतुलन को पुन: उत्पन्न कर सकता है।
- **नीतिगत व्यापार-बंद:** प्रभावी विनियमन को नौकरशाही चोक पॉइंट लगाए बिना पारदर्शिता, इक्विटी और बाजार दक्षता को संतुलित करना चाहिए।

नीति का महत्व

- **न्यायसंगत लाभ-साझाकरण:** स्थानीय समुदायों को वित्तीय पुरस्कार वितरित करने के लिए पारदर्शी तंत्र को औपचारिक बनाना।
- **सामुदायिक सहमति:** परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में एफपीआईसी सुनिश्चित करना।
- **हितधारक जुड़ाव:** विश्वास बनाने के लिए किसानों, आदिवासी समुदायों और छोटे किसानों के साथ समावेशी परामर्श।
- **अनुकूली विनियमन:** हल्के, लचीले ढांचे जो भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शोषण को रोकते हैं।
- **कार्बन बाजार की अखंडता:** सुरक्षा उपाय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, सामाजिक वैधता बनाए रखते हुए निवेश को आकर्षित करते हैं।

रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
जलवायु कार्रवाई विश्वसनीयता	सामुदायिक अधिकारों की रक्षा विश्वास और बाजार की अखंडता को मजबूत करती है।
ग्रामीण आजीविका	उचित लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करता है कि जलवायु परियोजनाओं का समर्थन हो, स्थानीय समुदायों को कमजोर न करें।
निवेश आकर्षण	पारदर्शी, न्यायसंगत कार्बन बाजार निजी और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करते हैं।
सामाजिक न्याय	एफपीआईसी और भूमि अधिकार सुरक्षा उपायों को एकीकृत करने से कमजोर समूहों को हाशिए पर रखने से रोका जा सकता है।
वैश्विक नेतृत्व	भारत समानता और स्थिरता के साथ कम कार्बन वाली पहलों को डिजाइन करने में एक उदाहरण स्थापित कर सकता है।

आगे की चुनौतियाँ

- शक्ति विषमता और छोटे किसानों और आदिवासी समुदायों का हाशिए पर।
- प्रथागत अधिकारों और गांव के आम लोगों के साथ संभावित भूमि-उपयोग संघर्ष।
- लाभ-साझाकरण व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव।
- टॉप-डाउन प्रोजेक्ट इम्पोजिंग एक्सट्रैक्टिव मॉडल की नकल करने का जोखिम।

- नियामक ढांचे को हल्का और प्रभावी रखते हुए बाजार में भागीदारी सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना **कम कार्बन आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई** के लिए एक मार्ग प्रदान करती है, लेकिन सुरक्षा उपायों के बिना, यह कमजोर समुदायों को हाशिए पर रखने और निष्कर्षण प्रथाओं को दोहराने का जोखिम उठाती है। वैश्विक अनुभवों से सीखते हुए, भारत को **बाजार दक्षता बनाए रखते हुए सामुदायिक सहमति, न्यायसंगत लाभ-साझाकरण और पारदर्शी शासन** सुनिश्चित करना चाहिए। हितधारकों की भागीदारी के साथ एक संतुलित नियामक दृष्टिकोण, भारत को एक विश्वसनीय, न्यायसंगत और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण कार्बन बाजार बनाने में मदद करेगा - जो पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय दोनों को बढ़ावा देगा।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: 2025 में भारत-रूस तेल व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a) भारत ने 2025 में रूस से तेल आयात करना पूरी तरह से बंद कर दिया।

b) भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहता है, हालांकि जून-सितंबर 2025 के बीच कुछ PSU में आयात ~45% तक गिर गया है.

c) भारत ने ऊर्जा आयात के कारण अमेरिका पर जुर्माना शुल्क लगाया।

d) रूस अब भारत को तेल निर्यात नहीं करता है।

उत्तर : b)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न। भारत में कार्बन बाजारों से जुड़े संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों की जांच करें और सुरक्षा उपायों का सुझाव दें। **(250 शब्द)**

Page : 09 : GS 3 : Indian Economy / Prelims

बिहार, अपनी उपजाऊ भूमि और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद, भारत के सबसे अविकसित राज्यों में से एक बना हुआ है। जबकि कुछ लोग इसका श्रेय इसके लैंडलॉक भूगोल को देते हैं, एक करीबी विश्लेषण से पता चलता है कि संरचनात्मक, राजनीतिक और सामाजिक कारक अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कृषि उत्पादकता, औद्योगीकरण, राज्य की क्षमता और संसाधनों के उपयोग से संबंधित चुनौतियों ने ऐतिहासिक रूप से बिहार के विकास को बाधित किया है। इन गतिशीलताओं को समझना उन नीतियों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है जो राज्य के तुलनात्मक लाभों का लाभ उठाते हैं जबकि इसके विकासात्मक घाटे को दूर करते हैं।

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Is landlockedness the reason for Bihar's underdevelopment?

R. Nagaraj
Economist and retired professor from the Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai

Manindra Nath Thakur
Professor, Centre for Political Studies, JNU, Delhi

PARLEY

It is election season in Bihar. While the Opposition often speaks about the lack of development and industrialisation in the State, in its campaigns, the National Democratic Alliance, which is in power, argues that a change of government will bring back the 'Jungle Raj' of the earlier decade. What makes Bihar one of India's most underdeveloped States? Is landlockedness a reason for its underdevelopment, as some argue? R. Nagaraj and Manindra Nath Thakur discuss the question in a conversation moderated by **Saptaparno Ghosh**. Edited excerpts:

It is often argued that Bihar is disadvantaged because it is a landlocked State. Punjab and Telangana are landlocked as well, and they are doing relatively well. So how is being landlocked a constraint for Bihar?

R. Nagaraj: If you look at the success of Telangana, especially Hyderabad, it is mostly because of the tertiary sector; it has nothing to do with geography. If a State has an educated workforce and good infrastructure, being landlocked will not be an issue. Punjab, too, has a developed network of railways and roads, and has FCI (Food Corporation of India) godowns across the country to help with export of crops.

Manindra Nath Thakur: Let us look at Bihar's prominent exports: makhana, litchi, and corn. It has been difficult for Bihar to transport these items from Patna to West Bengal or to any port. These, alongside the vegetables Bihar exports, are perishable. Moreover, significant costs are incurred due to road transport; time and distance are crucial factors in agrarian exports. One way Bihar is attempting to resolve this issue is by launching projects along the Ganga. So, it is not that concerns about being landlocked are not genuine, but they cannot be cited as a major reason for the State's economic backwardness.

Prof. Nagaraj spoke of the tertiary sector; you spoke of agrarian exports. Bihar has been assessed as an agrarian economy. What should be its imperative going forward: industrialisation or agriculture?

MT: In the last 10 years, the Chief Minister has tried to engage with industrialists. However, industrialists have often raised concerns about access to ports, citing the need to spend more on transportation. Having said that, I do think that in this modern capitalist system, no society can think of surviving with just agricultural products. While Bihar should capitalise on its potential in terms of agricultural production and processing, it must ultimately transition to industry. Without that, there is no future.

A women shucks corn in Virpur village in Begusarai, Bihar. R.V. MOORTHY

RN: Before we think of high-technology and/or manufacturing industries, we should consider where the comparative advantage lies. Four-fifth of Bihar's labour force is in agriculture. But despite Bihar having fertile land and irrigation facilities, agricultural productivity is mostly less than the national average. Why is agriculture not picking up? That is the big question.

In the 1970s or 80s, a committee set up under the agricultural economist, S.R. Sen, was figuring out how to take the Green Revolution to the Indo-Gangetic belt. It came up with a plan for massive State investments in infrastructure and electrification to ensure that States have abundant water for the cultivation of wheat and rice. Surprisingly, the Green Revolution spread to the Malwa region of Madhya Pradesh rather than the Indo-Gangetic belt. We must understand what went wrong.

I think it will be both in Bihar's interest and the national interest to get basic wheat, rice, and sugarcane cultivation going. This way, western India will be burdened less; it can conserve more water and move to value-added crops.

MT: On the agrarian front, I don't think Bihar should repeat the mistake that Punjab made during the Green Revolution, which produced a water crisis. Although Bihar has abundant water, it may face the same consequences as Punjab if water is overused. Moreover, increasing agricultural production is linked with the heavy use of fertilizers and pesticides, creating a health crisis. Therefore, I don't support the shifting of agriculture to eastern India. Agriculture is not profitable anywhere in the world unless it is heavily supported by the State.

RN: Madhya Pradesh was also seen as a backward State. It does not have the same water resources as Bihar, yet the Green Revolution expanded there. Prosperity in the Malwa region is amazing. Therefore, I am sceptical about the idea that agriculture has no potential.

> It is not that concerns about being landlocked are not genuine, but they cannot be cited as a major reason for the State's economic backwardness.
> MANINDRA NATH THAKUR

So what do you think are the factors that contributed to Bihar's underdevelopment?

MT: Apart from what I have said, there are also notions that the Centre is not interested in Bihar's growth. The State, I think, is frozen in its transition from feudalism to capitalism. One of the reasons for this is the internal colonisation of the State. Earlier, Bihar supplied raw materials, but due to policies such as freight equalisation, it suffered significantly, and industries didn't develop locally, despite having the advantage of raw material availability. Bihar ultimately lost revenues and its natural advantage. Now, with a supply of labour from Bihar, nobody is interested in developing the State.

RN: A commodity where freight equalisation was done and which benefited eastern India was cement. Steel did not accrue the same advantage. Cement has heavy transport costs compared to steel so the freight equalisation policy for it helped eastern India.

Furthermore, why Biharis are leaving Bihar has no element of capitalist conspiracy. In fact, when investments in agriculture were made in Bihar, migration to Punjab declined. It is clear that if people have more options at home, they will not move out.

Literature often suggests that Bihar has a 'socialist hangover', and that entrepreneurship does not draw confidence.

RN: The socialist ideology in Bihar is often equated with caste politics and caste in general – basically, distributing limited resources across various castes. If the focus shifts to productive investment, it will do a lot of good for Bihar. Policy must focus on how to augment production rather than looking at redistributing the limited resources more equitably or in a manner that helps people stay in power.

MT: Bihar has never really followed the socialist model. It also failed to understand the logic behind India's shift to capitalism. Bihar is currently at a significant disadvantage. For any structural change, there must be a solid commitment to reinvestment by the Union government. Unless that is done, the transition to capital will not take place. With respect to migration, if there are good working conditions and a decent income, no Bihari would like to migrate. The amount of investment required to help Bihar move out of this 'frozen transition' phase has not been made. It could be linked to general societal politics. One argument, as Shaibal Gupta used to make, relates to the lack of a distinct Bihari identity. Or as Prashant Kishore says, of the concept of Bihari asmita.

Would special status be of any help to Bihar?

RN: I am not sure it would help. The bigger question relates to whether it will be utilised productively or not. Bihar lacks the state capacity to use it. Whereas, if you give the same money to Andhra Pradesh or Tamil Nadu, they will grab it and use it better.

Being among the poorest states, Bihar gets a considerable amount of resources from the Finance Commission on considerations of its backwardness and to bring greater equality among States. When those are not utilised, the money lapses. Many of these grants are performance-based – meaning the State must raise its own share of resources to access the full amount. This often doesn't happen in Bihar.

MT: If a good amount of money is invested, it would certainly be beneficial. However, no change will come unless we make sure that the money we reinvest is not appropriated by a small number of people – elites, politicians, and contractors. If the money is invested properly, it leads to capital formation. But this also requires a kind of social revolution, one that raises public awareness that these funds are not free gifts, but more like loans. People must understand that we need to rebuild and strengthen our society in order to repay that investment.

About state capacity – many funding packages include a clause requiring the state to contribute a portion of the investment. Now, suppose you give me ₹100 and tell me that I have add to it to utilise the amount. I can't do that as I don't have the money. In a way that amounts to forcing me not to use the money. The special status might be of help – it might remove these conditions and allow us to access the support without being held back by limited state capacity.

To listen to the full interview
Scan the code or go to the link
www.thehindu.com

समस्या अवलोकन

- **लैंडलॉक्ड तर्क:** बिहार के भूगोल को अक्सर व्यापार और औद्योगिक विकास के लिए बाधा के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालांकि, तेलंगाना और पंजाब जैसे अन्य भूमि से घिरे राज्यों ने सफलतापूर्वक औद्योगीकरण किया है, जिससे पता चलता है कि बुनियादी ढांचा, मानव पूंजी और संस्थागत क्षमता केवल भूगोल से अधिक मायने रखती है।
- **कृषि निर्यात:** मखाना, लीची और मक्का जैसी खराब होने वाली वस्तुओं को उच्च परिवहन लागत और लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आंशिक रूप से बाजार पहुंच के बारे में चिंताओं को उचित ठहराते हैं। गंगा के किनारे परियोजनाओं का उद्देश्य इन बाधाओं को कम करना है।

- **औद्योगीकरण बनाम कृषि:** बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान बनी हुई है, जिसमें कृषि में इसका श्रम का चार-पांचवां हिस्सा है। विशेषज्ञों का तर्क है कि दोहरी रणनीति के लिए - कृषि उत्पादकता में सुधार करना और धीरे-धीरे औद्योगिक और तृतीयक क्षेत्रों में संक्रमण करना।

मुख्य अवलोकन

- **कृषि उत्पादकता:** उपजाऊ भूमि और सिंचाई के बावजूद, बिहार राष्ट्रीय औसत से पीछे है। हरित क्रांति के दौरान राज्य के निवेश की कमी ने भारत-गंगा बेल्ट में आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रसार को सीमित कर दिया।
- **औद्योगिक बाधाएं:** माल ढुलाई समानीकरण नीतियों, आंतरिक उपनिवेशीकरण और ऐतिहासिक संसाधन निष्कर्षण ने स्थानीय औद्योगिक विकास में बाधा डाली। उद्योग अक्सर स्थानीय स्तर पर पुनर्निवेश किए बिना बिहार के सस्ते श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं।
- **सामाजिक और राजनीतिक कारक:**
  - समाजवादी और जाति-आधारित राजनीति ने उत्पादक निवेश पर संसाधनों के पुनर्वितरण को प्राथमिकता दी हो सकती है।
  - सीमित राज्य क्षमता और वित्त आयोग के अनुदानों का अकुशल उपयोग विकासात्मक पहलों में बाधा डालता है।
- **प्रवासन और मानव पूंजी:** प्रवासन एक पूंजीवादी साजिश के बजाय स्थानीय अवसरों की कमी की प्रतिक्रिया है। स्थानीय कृषि और उद्योग में निवेश प्रवासन को कम करता है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
भूगोल और विकास	बुनियादी ढांचे और संस्थागत क्षमता की तुलना में लैंडलॉकनेस कम निर्णायक है।
कृषि	उपजाऊ भूमि का कम उपयोग; उच्च मूल्य वाली फसलों और कृषि-प्रसंस्करण की संभावना।
औद्योगिक नीति	ऐतिहासिक उपेक्षा, माल ढुलाई नीतियां और कमजोर पुनर्निवेश औद्योगीकरण को सीमित करते हैं।
शासन और राज्य की क्षमता	अनुदान की उपलब्धता के बावजूद संसाधनों का अकुशल उपयोग विकास को बाधित करता है।
सामाजिक संरचना	जाति आधारित राजनीति उद्यमिता और निवेश के विश्वास को प्रभावित करती है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **आर्थिक कारक:** बिहार का पिछड़ापन भौगोलिक नहीं बल्कि संरचनात्मक है: कम कृषि उत्पादकता, कमजोर औद्योगिक आधार और खराब बुनियादी ढांचा।
- **संस्थागत बाधाएं:** सीमित राज्य क्षमता और धन का अप्रभावी उपयोग विकास में बाधा डालता है।
- **नीतिगत निहितार्थ:** निवेश को केवल विशेष दर्जा या अनुदान प्रदान करने के बजाय पूंजी निर्माण, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **सामाजिक गतिशीलता:** संसाधन आवंटन और जाति की राजनीति उत्पादक निवेश को प्रभावित करती है; उद्यमिता और सामाजिक जवाबदेही को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
- **तुलनात्मक सबक:** तेलंगाना और पंजाब जैसे अन्य भूमि से घिरे राज्य प्रदर्शित करते हैं कि शिक्षित कार्यबल, बुनियादी ढांचा और नीति अभिविन्यास भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकते हैं।

□□□□□ □□□□□□

नीति का महत्व

- **कृषि आधुनिकीकरण:** सिंचाई, मशीनीकरण और मूल्य वर्धित फसल प्रसंस्करण में निवेश करें।
- **औद्योगिक संवर्धन:** स्थानीय और बाहरी उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी और बुनियादी ढांचा प्रदान करें।
- **प्रभावी निधि उपयोग:** सुनिश्चित करें कि उत्पादक परिणामों के लिए वित्त आयोग के अनुदान और विशेष स्थिति निधियों का पुनर्निवेश किया जाए।
- **सामाजिक जागरूकता और शासन:** संसाधनों के विशिष्ट कब्जे को रोकने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।
- **संतुलित विकास:** रोजगार पैदा करने और पलायन को कम करने के लिए औद्योगीकरण के साथ कृषि में सुधार को जोड़ना।

रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
आर्थिक विकास	बिहार की क्षमता को खोलने के लिए भूगोल नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार महत्वपूर्ण हैं।
कृषि उत्पादकता	आधुनिकीकरण प्रवासन पर निर्भरता को कम कर सकता है और ग्रामीण आजीविका में सुधार कर सकता है।
औद्योगिक विकास	केंद्रित निवेश पूंजी को आकर्षित कर सकता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा कर सकता है।
सामाजिक समानता	न्यायसंगत पुनर्निवेश मानव पूंजी को मजबूत करता है और अभिजात वर्ग के कब्जे को कम करता है।
राज्य की क्षमता	विशेष स्थिति निधि का उपयोग करने के लिए संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

आगे की चुनौतियाँ

- उपजाऊ भूमि के बावजूद कम कृषि उत्पादकता।
- औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे की ऐतिहासिक उपेक्षा।
- जाति आधारित राजनीति संसाधनों के आवंटन को प्रभावित कर रही है।
- सीमित राज्य क्षमता और अकुशल निधि उपयोग।
- स्थानीय अवसरों की कमी के कारण पलायन जारी है।

निष्कर्ष:

बिहार के अविकसितता को केवल इसके भू-परिवेक्षण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। राज्य को संरचनात्मक, संस्थागत और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो विकास में बाधा डालते हैं। कृषि उत्पादकता, औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे और राज्य की क्षमता में सुधार, संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ, बिहार की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। विशेष स्थिति या अनुदान मदद कर सकते हैं यदि उत्पादक रूप से पुनर्निवेश किया जाता है, लेकिन सतत विकास के लिए पूंजी निर्माण, कौशल विकास और सामाजिक जवाबदेही की दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता होती है। केवल भूगोल ही नियति नहीं है; संस्थागत प्रभावशीलता और नीति अभिविन्यास निर्णायक हैं।

□□□□□ □□□□□□

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न : बिहार के आर्थिक भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बिहार एक भूमि से घिरा हुआ राज्य है और बंदरगाहों तक सीधी पहुंच का अभाव है।

2. गंगा के उपजाऊ मैदानों के कारण बिहार में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक कृषि उत्पादकता है।

3. राज्य के नेतृत्व वाले सिंचाई निवेश के कारण बिहार के भारत-गंगा क्षेत्र में हरित क्रांति व्यापक रूप से फैल गई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2 और 3

उत्तर: a)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: लैंडलॉक होने के बावजूद, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हासिल किया है, जबकि बिहार लगातार पिछड़ रहा है। बिहार के अविकसितता के लिए जिम्मेदार कारकों की आलोचनात्मक जांच कीजिए। **(150 शब्द)**

Page 10 : GS 2 : Indian Polity / Prelims

2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से भारत के संघीय राजकोषीय ढांचे में संरचनात्मक बदलाव हो रहे हैं । जबकि जीएसटी का उद्देश्य एक एकीकृत कर व्यवस्था बनाना और दक्षता में सुधार करना है, इसने कराधान शक्ति को भी केंद्रीकृत किया है, जिससे राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता बाधित होती है। जीएसटी मुआवजा उपकर का हालिया उन्मूलन एक संक्रमणकालीन युग के अंत का प्रतीक है, जिससे राज्य वित्त, संसाधन वितरण और सहकारी संघवाद पर चिंताएं बढ़ गई हैं। जैसे-जैसे जनता की अपेक्षाएं और सेवा वितरण जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, कराधान पर केंद्र के नियंत्रण और राज्यों के व्यय दायित्वों के बीच असंतुलन तेजी से दिखाई देने लगा है।

Restoring fiscal space for the States

With rising public aspirations and widening service gaps, States' expenditure commitments are steadily increasing; GST introduction has altered the resource position of the States, in addition to centralising the authority to levy tax

समस्या अवलोकन

- **GST मुआवजे का अंत:**
  - नियमित करों के साथ मुआवजा उपकर का विलय पांच साल के राजस्व संरक्षण तंत्र की निष्कर्ष का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत में राज्यों को गारंटी दी गई थी।
  - जबकि केंद्र का तर्क है कि राज्यों को मुआवजे के माध्यम से लाभ हुआ है, कई राज्यों को अनुमान से अधिक राजस्व हानि और राजकोषीय सुरक्षा उपायों की कमी का डर है।
- **कर शक्ति का केंद्रीकरण:**
  - जीएसटी के बाद, कराधान की शक्ति प्रभावी रूप से अलग-अलग राज्यों से जीएसटी परिषद में स्थानांतरित हो गई है, जहां केंद्र का प्रभुत्व है।
  - विभाज्य कर पूल के बाहर उपकर और अधिभार तंत्र, केंद्र के राजकोषीय लाभ को और मजबूत करता है।
- **राज्य व्यय की बढ़ती प्रतिबद्धताएँ:**
  - राज्य प्रमुख कल्याण और शासन क्षेत्रों - स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कानून और व्यवस्था, और स्थानीय सरकार के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करते हैं - जिससे राजस्व लचीलेपन के बिना व्यय बढ़ता है।

□□□□□ □□□□□□

संवैधानिक और संस्थागत ढांचा

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 246, 268-293 केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों को परिभाषित करते हैं।
  - अनुच्छेद 280 कर हस्तांतरण और अनुदान की सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग (FC) की स्थापना करता है।
  - अनुच्छेद 275 और 282 क्रमशः वैधानिक और विवेकाधीन अनुदान प्रदान करते हैं।
- **राजस्व साझाकरण का विकास:**
  - 11वें से 14वें वित्त आयोग तक, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 29.5 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई, जिसे बाद में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद समायोजित कर दिया गया।
  - हालांकि, सकल कर राजस्व (जीटीआर) के हिस्से के रूप में वास्तविक हस्तांतरण में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण उपकरों और अधिभारों पर केंद्र की बढ़ती निर्भरता है, जो राज्यों के साथ साझा करने योग्य नहीं हैं।

मुख्य अवलोकन

दृष्टिकोण	कथन
जीएसटी शासन प्रभाव	जीएसटी परिषद के माध्यम से कराधान की शक्ति केंद्र को हस्तांतरित की गई; राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता का क्षरण हुआ।
गिरता हस्तांतरण हिस्सा	वित्त आयोग की उच्च सिफारिशों के बावजूद, उपकरों/अधिभारों को शामिल नहीं किए जाने के कारण वास्तविक अंतरण में देरी होती है।
केंद्र पर निर्भरता	केंद्रीय हस्तांतरण पर राज्यों की निर्भरता औसतन 44% है, जिसमें बिहार जैसे गरीब राज्य 72% तक निर्भर हैं।
राजकोषीय विषमता	केंद्र अधिकांश राजस्व को नियंत्रित करता है; व्यय की अधिकांश जिम्मेदारी राज्य वहन करते हैं।
वित्त आयोग की चिंताएं	मानदंड और भार में असंगति प्रगतिशील राज्यों को दंडित करती है।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)	सीएसएस के विस्तार से केंद्र का खर्च बढ़ता है लेकिन यह राज्य के विषयों के साथ ओवरलैप होता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- डिजाइन विषमता: भारत की राजकोषीय प्रणाली ऊर्ध्वाधर असंतुलन प्रदर्शित करती है - केंद्रीकृत राजस्व संग्रह और विकेंद्रीकृत खर्च जिम्मेदारियां। जीएसटी के बाद के ढांचे ने इस बेमेल को बढ़ा दिया है।
- सवालों में सहकारी संघवाद: राज्यों के लिए राजकोषीय स्थान का क्षरण सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है, विशेष रूप से विपक्ष शासित राज्यों में जो धन प्रवाह में अनिश्चितता का सामना करते हैं।
- अक्षम संसाधन उपयोग: योजना-आधारित वित्त पोषण में जटिल हस्तांतरण तंत्र और राजनीतिक विवेक पारदर्शिता और जवाबदेही को कम करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय तुलना (कनाडा मॉडल): कनाडा अधिक राजकोषीय स्वायत्तता की अनुमति देता है - प्रांत 54% राजस्व एकत्र करते हैं और 60% खर्च करते हैं, सेवा वितरण में लचीलापन और स्वामित्व सुनिश्चित करते हैं।

नीतिगत निहितार्थ और सुधार विकल्प

सुधार क्षेत्र	अनुशंसित उपाय
टैक्स बेस शेयरिंग का विस्तार करें	राज्यों को केंद्र के साथ 50:50 के आधार पर व्यक्तिगत आयकर साझा करने या टॉप-अप करने की अनुमति दें।
डिवोल्यूशन फॉर्मूला पर फिर से गौर करें	यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग के दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए कि प्रगतिशील राज्यों को दंडित न किया जाए।
उपकर और अधिभार का विलय	निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन्हें विभाज्य पूल में लाएं।
जीएसटी परिषद के राज्यों को सशक्त बनाना	निर्णय लेने में मतदान समानता और प्रतिनिधित्व बढ़ाएँ।
सीएसएस को तर्कसंगत बनाना	राज्यों को संवैधानिक रूप से सौंपे गए विषयों में केंद्रीय हस्तक्षेप को सीमित करना।
पारदर्शिता तंत्र	निधि आवंटन और प्रदर्शन-आधारित अनुदानों का सार्वजनिक प्रकटीकरण।

स्थिर और वर्तमान संपर्क

स्थैतिक विषय (राजनीति और अर्थव्यवस्था)	वर्तमान प्रासंगिकता
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध	जीएसटी और उपकर संरचना राजकोषीय संघवाद संतुलन को बदल देती है।
वित्त आयोग	जीएसटी के बाद ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण में भूमिका महत्वपूर्ण है।
सहकारी संघवाद	राजकोषीय स्वायत्तता का क्षरण इस सिद्धांत को चुनौती देता है।
राजकोषीय समेकन	राज्यों की उधार सीमा और घाटे व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं।
कर नीति	आयकर बंटवारे और जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने पर बहस तेज हो गई है।

आगे की चुनौतियाँ

- सीमित राजस्व नियंत्रण के साथ बढ़ती व्यय जिम्मेदारियां।
- राजकोषीय स्वायत्तता और मुआवजे को लेकर राजनीतिक घर्षण।
- केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता तरलता जोखिम पैदा करती है।
- वित्त आयोग के मानदंड और सीएसएस फंडिंग में असंगति।
- उभरते राजकोषीय परिदृश्य के बीच गतिशील संघीय समायोजन की आवश्यकता।

रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
आर्थिक स्थिरता	राजकोषीय असंतुलन राष्ट्रीय विकास और राजकोषीय अनुशासन पर दबाव डाल सकता है।
संघीय शासन	राज्यों की विवश स्वायत्तता सहकारी संघवाद को कमजोर कर सकती है।
सेवा वितरण	राजस्व सीमाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं।
राजकोषीय नवाचार	आयकर आधार साझा करने या राज्य-स्तरीय अधिभार बनाने से दक्षता बढ़ सकती है।

□□□□□ □□□□□□

निष्कर्ष:

भारत का राजकोषीय संघवाद एक चौराहे पर खड़ा है। जबकि जीएसटी ने कराधान को सुव्यवस्थित किया है और अनुपालन में सुधार किया है, इसने राजकोषीय प्राधिकरण को भी केंद्रीकृत किया है, जिससे राज्यों की स्वतंत्र रूप से संसाधन जुटाने की क्षमता सीमित हो गई है। सार्वजनिक आकांक्षाओं के बढ़ने और सेवा मांगों के व्यापक होने के साथ, राज्यों के लिए राजकोषीय स्थान को बहाल करना न केवल एक आर्थिक आवश्यकता है, बल्कि एक राजनीतिक अनिवार्यता है। संशोधित हस्तांतरण सूत्रों, पारदर्शी हस्तांतरण और आंशिक कर स्वायत्तता के माध्यम से राज्यों को सशक्त बनाने से सहकारी संघवाद को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि विकास संतुलित, समावेशी और सही मायने में संघीय बना रहे।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए गए विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है?

(a) आयकर

(b) निगम कर

(c) उपकर और अधिभार

(d) सीमा शुल्क

उत्तर : c)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: लगातार वित्त आयोगों द्वारा उच्च हस्तांतरण की सिफारिश करने के बावजूद, राज्यों को राजकोषीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रवृत्ति के कारणों का विश्लेषण करें और राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता बढ़ाने के उपाय सुझाएं। **(150 शब्द)**

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□ □□□□□□

Page : 08 Editorial Analysis

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

A reading of a revisionism in constitutional history

Sanjay Hegde

is a Senior Advocate designated by the Supreme Court of India

A quiet revisionism in constitutional history is being seeded. Some commentators now argue that Sir Benegal Narsing Rau, the Constitutional Adviser to the Constituent Assembly, was the real architect of India's Constitution, while Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, the Chairman of the Drafting Committee, merely polished an already finished product. This argument may sound academic, but it is not. It represents an attempt to diminish Dalit agency in India's founding story and to erase the moral force that B.R. Ambedkar brought to the making of the Republic.

Complementary, not competing

Both men were indispensable to the Constitution's creation, but their roles were entirely different. Sir B.N. Rau, a distinguished civil servant and jurist, was appointed Constitutional Adviser in July 1946. His assignment was technical and preparatory. Rau had in British India, helped in the drafting of the Government of India Act of 1935. Eleven years later, he had to prepare a working draft of the Constitution based on reports of the Constituent Assembly's committees and his study of other constitutions. He examined the American, Canadian, Irish, Australian and Weimar models, and consulted jurists such as Felix Frankfurter and Harold Laski. In October 1947, he submitted his draft with 243 articles and 13 schedules. Rau's document provided the Assembly with a starting point. He had no seat in the Constituent Assembly and no political mandate. His authority was scholarly, not representative.

Ambedkar's task was of a different order. As Chairman of the Drafting Committee, he had to turn a legal draft into a political covenant. He carried the Constitution through the turbulence of Partition, the murder of the Mahatma and had to defend its provisions, clause by clause, in the Assembly. His responsibility was not only to refine the text but also to build consensus among sharply divided interests. Rau built the framework. Ambedkar made it a living instrument of justice.

Ambedkar never denied Rau's contribution. In his concluding address to the Constituent Assembly on November 25, 1949, he said: "The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir B.N. Rau, the Constitutional Adviser to the Constituent Assembly who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the Drafting Committee."

He also said, "A part of the credit must go to the members of the Drafting Committee who, as I have said, have sat for 141 days... Much greater share of the credit must go to Mr. S.N. Mukherjee, the Chief Draftsman of the Constitution. His ability to put the most intricate proposals in the simplest and clearest legal form can rarely be equalled, nor his capacity for hard work."

Thus the words which are often used to claim that Rau, not Ambedkar, was the real author of the Constitution in fact, show the opposite. Ambedkar called Rau's work a "rough draft", not a finished text. The Drafting Committee and the Assembly turned that raw material into the document that finally came into force in January 1950. Nor does any evidence exist to show that Rau ever claimed to be the Constitution's author. His correspondence at that time with Ambedkar and Jawaharlal Nehru conveys respect and cooperation. The current effort to crown him as "Father of the Constitution" distorts both the record and Rau's own modesty.

The political motive

The campaign to elevate Rau and sideline Ambedkar is not driven by scholarship alone. It reflects a discomfort with the idea that a Dalit thinker could stand at the centre of the Republic's founding moment. Recasting Rau as the Constitution's principal author is an attempt to reclaim authorship for caste privilege. It tames Ambedkar's radical legacy and turns a social revolution into a bureaucratic exercise. The Constitution is not a sterile legal document. It is, first and foremost, a social manifesto which promises the dignity of the individual. It was born out of conflict, hope and redemption. It represented the arrival of the oppressed at the table of power. To detach Ambedkar from it is to rob it of its soul.

Ambedkar's presence in the Constituent Assembly was itself the result of a decisive act of political wisdom. He had originally been elected from Bengal, but after Partition, that seat went to Pakistan. Many within the Congress were hesitant to bring him back because of past disagreements. It was Mahatma Gandhi's intervention that settled the question.

Though Gandhi and Ambedkar had clashed over separate electorates, Gandhi insisted that Ambedkar must be part of the Assembly. He told Congress leaders that no Constitution could claim legitimacy if the Scheduled Castes were excluded from its making.

As a result, Ambedkar was re-elected from the Bombay Presidency. Gandhi's insistence was an act of foresight. In 1947, when the nation was fractured by religion, an alienated Dalit leadership could have deepened the divide. By ensuring Ambedkar's inclusion, Gandhi prevented a crisis that could have weakened the new Republic at its birth. Ambedkar's subsequent leadership proved that inclusion right. He turned the making of the Constitution into a moral enterprise that bound the country together.

Rau's draft provided the order and structure. Ambedkar gave the Constitution its moral depth. The provisions on Fundamental Rights, Directive Principles, and affirmative action bear his imprint. His speeches in the Assembly made the Constitution a living moral philosophy.

Ambedkar warned that political equality would fail without social and economic equality. He said, "How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up." That warning still remains the most powerful moral statement in India's constitutional history.

The peril of forgetting

Every Republic must guard its memory. The attempt to raise Rau above Ambedkar is part of a larger effort to drain the Constitution of its radical spirit. It presents the founding as a matter of technical competence rather than social transformation. To honour Ambedkar is not to diminish Rau. Both served the Republic faithfully. But the Constitution is more than a legal framework. It is a statement of national purpose. It needed a scholar's precision, but it also needed a reformer's conviction. Ambedkar was that reformer.

When the Constitution was adopted, leaders across the political spectrum, including Nehru, Patel and Prasad, publicly acknowledged Ambedkar's central role. None suggested that Rau was the Constitution's principal author. They understood the difference between drafting a text and shaping a nation's conscience.

Rau deserves admiration as a brilliant adviser. Ambedkar deserves reverence as the Constitution's moral architect. The Constitution was not written in the calm of colonial offices but in the shadow of Partition, the Mahatma's assassination and caste oppression. To place Ambedkar at its centre was not symbolic generosity but a statement that India's new order would belong equally to those once excluded.

Ambedkar never claimed sole authorship. Yet, his leadership of the Drafting Committee, his defence of every clause, and his vision of liberty, equality and fraternity have defined the Indian Republic. To diminish his role is to betray the Republic's founding promise. Rau built the structure; Ambedkar filled it with justice. Sir B.N. Rau deserves gratitude as the constitutional engineer. Dr. B.R. Ambedkar remains the architect and moral founder of modern India.

To deny that truth is to deny the Republic.

The campaign to elevate B.N. Rau and sideline B.R. Ambedkar as the real architect of India's Constitution is misplaced

GS. Paper 2- भारतीय राजनीति

UPSC Mains Practice Question: बीएन राव को संवैधानिक लेखकत्व में बीआर अंबेडकर पर ऊपर उठाने का प्रयास भारत के राष्ट्र-निर्माण में दलित एजेंसी के साथ एक बड़ी असुविधा को दर्शाता है। चर्चा करें। **(150 शब्द)**

संदर्भ:

वैश्विक आर्थिक व्यवस्था एक भूकंपीय परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जो अमेरिका-चीन महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता, लोकलुभावन-निरंकुश शासन और तकनीकी बदलावों से प्रेरित है। उदार वैश्वीकरण के पारंपरिक मानदंडों को राज्य-केंद्रित पूंजीवाद, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और भू-राजनीतिक पुनर्गणना द्वारा चुनौती दी जाती है, जो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए जोखिम और अवसर दोनों पैदा करते हैं।

- लोकलुभावन-निरंकुश कुलीन वर्ग और क्रोनी-पूंजीपतियों को प्राथमिकता देते हैं, अक्सर सामाजिक अनुबंधों को कमजोर करते हैं।
- अमेरिकी रणनीतिक और आर्थिक कार्रवाइयां (टैरिफ, प्रतिबंध, आपूर्ति श्रृंखला प्रतिभूतीकरण, डिजिटल मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र) वैश्विक व्यापार, वित्त और तकनीकी परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं।
- बिग टेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मूल्य श्रृंखलाओं, राजनीतिक परिणामों और आर्थिक संप्रभुता को प्रभावित करते हैं।
- वैश्विक दक्षिण राष्ट्र द्विपक्षीय संधियों, उत्पादन के स्थानीयकरण, डी-डॉलरीकरण और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से विकल्प तलाश रहे हैं।
- ऐतिहासिक रूप से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले भारत और चीन के पास अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था बनाने की खिड़की है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता/लिंक
वैश्वीकरण और आर्थिक शासन	अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता और लोकलुभावन-निरंकुश लोगों द्वारा बाधित नवउदारवादी मानदंड।
डिजिटल वित्त और एआई	स्विफ्ट सिस्टम, एआई एक्शन प्लान, डिजिटल मुद्राएं व्यापार और संप्रभु स्वायत्तता को प्रभावित करती हैं।
ऋण और विकास	सहायता में कटौती और संरचनात्मक समायोजन बाधाएं कमजोर देशों को नुकसान पहुंचाती हैं।

□□□□□ □□□□□□

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता/लिंक
ग्लोबल साउथ सहयोग	ब्रिक्स, दक्षिण-दक्षिण साझेदारी और नए व्यापार/ऋण ढांचे विकल्प प्रदान करते हैं।
घरेलू नीति और राज्य की भूमिका	राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. **महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता और भू-आर्थिक बदलाव**
   - अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन, दुर्लभ पृथ्वी प्रतिभूतिकरण और संरक्षणवादी उपायों को चलाती है।
   - उभरते संघर्ष, प्रतिबंध और व्यापार युद्ध पारंपरिक उदार व्यवस्था को बाधित करते हैं।
2. **डिजिटल और वित्तीय प्रतिमान**
   - बिग टेक और एआई मूल्य निष्कर्षण, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक निर्भरता को नया आकार देते हैं।
   - राज्य समर्थित डिजिटल मुद्राएं राष्ट्रीय संप्रभुता और एएमएल ढांचे को कमजोर कर सकती हैं।
3. **ग्लोबल साउथ के लिए अवसर**
   - रणनीतिक स्थानीयकरण, ऋण राहत ढांचे और दक्षिण-दक्षिण गठबंधन देशों को वैश्विक अर्थशास्त्र में एजेंसी का दावा करने की अनुमति देते हैं।
   - भारत वैश्विक संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व और सतत विकास की वकालत करते हुए एक नए आर्थिक समझौते का नेतृत्व कर सकता है।
4. **घरेलू पुनर्गणना अनिवार्यता**
   - राज्य को ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल वित्त को प्राथमिकता देनी चाहिए।
   - सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और संप्रभु धन-कोष रणनीतिक राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं।
   - एकाधिकार-विरोधी मानदंड और अनुसंधान एवं विकास निवेश वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

रणनीतिक निहितार्थ

- राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता: रणनीतिक क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करती है।
- वैश्विक नेतृत्व: भारत एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था को आकार दे सकता है और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ा सकता है।
- आर्थिक लचीलापन: विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं, संप्रभु नियंत्रण और रणनीतिक निवेश वैश्विक उथल-पुथल से बचाते हैं।
- डिजिटल और तकनीकी बढ़त: एआई, क्लाउड और डिजिटल फाइनेंस का उपयोग भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को मजबूत करता है।

चुनौतियों

1. वैश्विक अनिश्चितता: महाशक्ति संघर्ष और लोकलुभावन नीतियां अस्थिरता को बढ़ाती हैं।
2. डिजिटल उपनिवेशीकरण: विदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे पर निर्भरता आर्थिक संप्रभुता को जोखिम में डालती है।
3. घरेलू कार्यान्वयन: मजबूत राज्य कार्रवाई के लिए नीतिगत निरंतरता, द्विदलीय सहमति और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की आवश्यकता होती है।

4. ऋण और सहायता अंतराल: कमजोर अर्थव्यवस्थाएं विकास सहायता में गिरावट के कारण विवश हैं।
5. भू-राजनीतिक दबाव: स्वायत्तता से समझौता किए बिना कई वैश्विक अभिनेताओं के साथ जुड़ना।

निष्कर्ष:

वर्तमान में चल रहा वैश्विक आर्थिक परिवर्तन भारत को आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने, घरेलू संस्थानों को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ को अधिक न्यायपूर्ण और स्थिर विश्व व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए एक रणनीतिक खिड़की प्रदान करता है। राज्य के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप, रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उत्तोलन और वैश्विक साझेदारी के संयोजन से, भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि उभरते भू-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में रचनात्मक भूमिका भी निभा सकता है।

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 6TH OCT 2025
PSIR
MENTORSHIP BY-NITIN KUMAR SIR
COMPREHENSIVE COVERAGE (4-5 MONTHS)
DAILY CLASSES : 2 hrs. (ONLINE CLASS)
350+ HRS . MAXIMUM: 40 STUDENTS PER BATCH.
PERIODIC DOUBT SESSION & CLASS TEST
16 SECTIONAL TEST (4 FROM EACH SECTION)
4 FULL LENGTH TEST
CHAPTERWISE PYQS DISCUSSION
CHAPTERWISE COMPILATION OF QUOTATION
DAILY ANSWER WRITING
ONE TIME PAYMENT
RS 25,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 30,000/-
www.nitinsirclasses.com
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

THE HINDU

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR
CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)
DURATION : 7 MONTH
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
TEST SERIES WITH DISCUSSION
DAILY THE HINDU ANALYSIS
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES
DOUBT SESSIONS
ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

सफलता बैच (Pre 2 Interview)

- DURATION : 1 YEAR
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)

ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

आधार बैच (Aadhaar Batch)

- DURATION : 2 YEARS
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- NCERT FOUNDATION
- SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES

ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

Nitin sir classes
Know your daily
CLASSES
TIME TABLE FOR DAILY CLASSES
• 07:30 PM - THE HINDU ANALYSIS
• 09:00 PM - Daily Q & A Session (PT + Mains)
SUBSCRIBE
HTTPS://T.ME/NITIN KUMAR (PSIR)
WWW.NITINSIRCLASSES.COM

NITIN SIR CLASSES
KNOW YOUR TEACHERS
Nitin sir Classes
HISTORY + ART AND CULTURE
GS PAPER I
ASSAY SIR
SHIVENDRA SINGH
SOCIETY + SOCIAL ISSUES
GS PAPER I
NITIN KUMAR SIR
SHABIR SIR
POLITY + GOVERNENCE + IR + SOCIAL JUSTICE
GS PAPER II
NITIN KUMAR SIR
GEOGRAPHY
GS PAPER I
NARENDRA SHARMA SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
ANUJ SINGH SIR
ECONOMICS
SCI & TECH
GS PAPER III
SHARDA NAND SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
INTERNAL SECURITY + ENG. (MAINS)
GS PAPER III
ARUN TOMAR SIR
ENVIRONMENT & ECOLOGY AND DISASTER MANAGEMENT
GS PAPER III
DHIPRAGYA DWIVEDI SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
ETHICS AND APTITUDE + ESSAY + CURRENT AFFAIRS
GS PAPER IV
NITIN KUMAR SIR
CSAT
YOGESH SHARMA SIR
HISTORY
OPTIONAL
ASSAY SIR
SHIVENDRA SINGH
GEOGRAPHY
OPTIONAL
NARENDRA SHARMA SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
PSIR + PUBLIC ADMINISTRATION
OPTIONAL
NITIN KUMAR SIR
SOCIOLOGY
OPTIONAL
SHABIR SIR
HINDI LITERATURE
OPTIONAL
PANKAJ PARMAR SIR
https://www.facebook.com/ nitinsirclasses
https://www.youtube.com/@nitinsirclasses8314
http://instagram.com/k.nitinca
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)

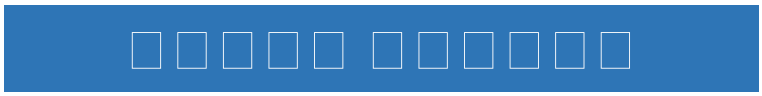

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**